



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

20 ज्येष्ठ 1937 (श0)  
(सं0 पटना 631) पटना, बुधवार, 10 जून 2015

---

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

21 मई 2015

सं0 22/नि0सि0(पू0)—01—12/2009/1211—श्री अख्तर आलम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के द्वारा बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार के विरुद्ध बाढ़ संघर्षात्मक कार्य में लापरवाही बरते जाने के कारण स्पर एवं तटबंध के क्षतिग्रस्त होने के आरोप में विभागीय आदेश संख्या 3294 दिनांक 26.08.09 द्वारा निलंबित किया गया, पुनः अधिसूचना ज्ञापांक 1634 दिनांक 04.11.10 द्वारा निलंबन से मुक्त किया गया। तदोपरान्त श्री अख्तर आलम के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत संकल्प ज्ञापांक 980 दिनांक 08.08.11 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के क्रम में ही श्री अख्तर आलम के दिनांक 31.07.12 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) में अधिसूचना ज्ञापांक 1426 दिनांक 24.12.12 द्वारा सम्प्रतिवर्तित किया गया। जाँचोपरान्त संचालन पदाधिकारी ने पत्रांक 3994 दिनांक 05.12.11 द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया, उक्त जाँच प्रतिवेदन में श्री आलम के विरुद्ध लगाये गये आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी, सम्यक समीक्षोपरान्त जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए श्री आलम से विभागीय पत्रांक 161 दिनांक 07.02.13 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री आलम से प्राप्त जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि बाढ़, 2009 में लाभा पहाड़पुर महानंदा दायौ तटबंध के चेन संख्या 688 पर अवस्थित स्पर एवं उनके डाउन स्ट्रीम में तटबंध क्षतिग्रस्त होने के लिए श्री अख्तर आलम पूर्ण रूप से दोषी हैं।

अतः सम्यक समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री अख्तर आलम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया:-

1. 30% पेंशन पर 10 (दस) वर्षों तक रोक।
2. निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जाएगी।

अतएव सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में श्री अख्तर आलम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार सम्प्रति सेवानिवृत्त को निम्न दण्ड संसूचित किया जाता है-

1. 30% पेंशन पर 10 (दस) वर्षों तक रोक।
2. निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जाएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
सतीश चन्द झा,  
सरकार के अपर सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 631-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>